Drishti IAS

करेंट अफेयर्स राजस्थान

अगस्त (संग्रह)

2023

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

राजस्थान **3**

- राजस्थान प्रीमियर लीग की शुरुआत 19 अगस्त से 3
- प्रदेश में समग्र शिक्षा कार्यक्रमों की गाइडलाइन के इंटरैक्टिव वीडियो तैयार 3
- राजस्थान विधानसभा में कई महत्त्वपूर्ण विधेयक ध्वनिमत से पारित 5
- राज्यपाल ने 'संविधान को पढ़ो और जिओ'अभियान की शुरुआत की 6
- 'तारबंदी योजना' में प्रदेश पूरे देश में अव्वल 7
- अंगदान महाअभियान की शुरुआत 7
- नेशनल हैंडलूम वीक-2023 9
- इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट- राजस्थान को मिला बेस्ट हेरिटेज टूरिज़्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवॉर्ड 11
- मुख्यमंत्री ने दी स्वीकृति- राजस्थान राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड का हुआ गठन 11

The Vision

नोट :

राजस्थान

राजस्थान प्रीमियर लीग की शुरुआत 19 अगस्त से

चर्चा में क्यों ?

1 अगस्त, 2023 को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने जयपुर में इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की तर्ज पर राजस्थान प्रीमियर लीग (आरपीएल) की शुरुआत 19 अगस्त से होने की औपचारिक घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने बताया कि 19 अगस्त से जोधपुर में शुरू होने वाले आईपीएल में छह टीम हिस्सा लेंगी। इसके लिये एक अगस्त से टीम की खरीद के लिये बिड शुरू की जाएगी। टीम को खरीदने के लिये बोली लगानी होगी।
- वैभव गहलोत ने बताया कि छह टीमें- जयपुर, जोधपुर, सीकर, कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर के लिये बड़े उद्योग घराने बोली लगाएंगे।
- इन टीमों में सात इंटरनेशनल खिलाड़ी और 10 आईपीएल के खिलाड़ी भी राजस्थानी खिलाड़ियों के साथ खेलते नज़र आएंगे।
- सभी मैच अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होंगे, जो जयपुर और जोधपुर के स्टेडियम में खेले जाएंगे। एक दिन में दो मैच होंगे। एक दिन के उजाले में और दूसरा दूधिया रोशनी में खेला जाएगा। कुल 34 मैच खेले जाएंगे, प्रत्येक मैच 20 ओवर का होगा।
- वैभव गहलोत ने बताया कि आईपीएल की ट्रॉफी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, जिसके लिये चांदी की ट्रॉफी पर सोने का काम किया गया है।

प्रदेश में समग्र शिक्षा कार्यक्रमों की गाइडलाइन के इंटरैक्टिव वीडियो तैयार

चर्चा में क्यों ?

2 अगस्त, 2023 को राजस्थान के स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि प्रदेश में विभाग द्वारा अनूठी पहल के तौर पर समग्र शिक्षा अभियान के तहत संचालित कार्यक्रमों, गतिविधियों और 'टीचर्स ट्रेनिंग मॉड्यूल'के वीडियो तैयार कराए गए हैं। इनको आगामी दिनों में वॉट्सएप ग्रुप के माध्यम से सभी सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को सर्कुलेट कर दिया जाएगा।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि इसके तहत करीब चार दर्जन गाइडलाइंस को 15 इंटरेक्टिव वीडियोज में समाहित कर 'यूट्यूब' पर अपलोड कर इनके 'क्यूआर कोड'बनाए गए हैं।
- इस नई पहल से शिक्षक, अभिभावक, आमजन और विद्यार्थी अपने से संबंधित कार्यक्रमों की जानकारी चंद मिनटों में मोबाईल पर 'क्यूआर कोड'को स्कैन करते हुए इन वीडियोज़ के ज़रिये प्राप्त कर सकेंगे।
- इस प्रयोग से विभागीय गतिविधियों का और अधिक पारदर्शिता के साथ संचालन होगा और इनमें सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। वीडियो के रूप में प्रसारित गाइडलाइन को पढ़ने और समझने में आसानी रहेगी, जिससे विभागीय योजनाओं का प्रभावी संचालन हो सकेगा।
- उन्होंने बताया कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत अलग-अलग कार्यक्रमों की गाइडलाइन को समय-समय पर विभागीय सर्कुलर के माध्यम से जारी किया जाता है। इस परंपरागत तरीके से जारी किये जाने वाले दिशा-निर्देश प्राय: अधिकारियों और प्रिंसिपल तक ही सीमित रह जाते हैं।
- इस दिशा में विभाग द्वारा 'लीक से हटकर'कार्य करते हुए सभी 'गाइडलाइंस'की समीक्षा की गई। इनके व्यावहारिक और एक समान पहलुओं को जोड़कर 'ऑडियो-विज़ुअल फॉर्म'में बदलते हुए 'इंटरैक्टिव वीडियोज़'तैयार किये गए हैं। इन वीडियो को 'यूट्यूब'पर अपलोड कर उनके 'क्यू आर कोड'बनाए गए हैं।
- इनको विभाग के तहत संभाग, ज़िला, ब्लॉक एवं स्कूलों के स्तर पर अधिकारियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों के 'वॉट्सएप ग्रुप'द्वारा राज्य के समस्त सरकारी स्कूलों तक सुलभ करा दिया जाएगा।
- अलग-अलग थीम पर बनाए उपयोगी वीडियोज़
  - स्कूल शिक्षा विभाग के सभी 'स्टेकहोल्डर्स'के लिये उपयोगिता और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ये वीडियोज़ अलग-अलग थीम पर तैयार कराए गए हैं।
  - 'ग्रांट्स फॉर स्कूल'के वीडियो में कंपोजिट स्कूल ग्रांट एवं स्पोर्ट्स ग्रांट, 'क्लब्स इन द स्कूल' में यूथ एंड इको क्लब एवं विज्ञान क्लब, 'स्कूल उत्सव'शीर्षक पर बने वीडियो में प्रवेशोत्सव, वार्षिकोत्सव, एल्यूमिनाई मीट, बाल समारोह, कला उत्सव एवं रंगोत्सव तथा 'हॉस्टल्स'के वीडियो में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं मेवात बालिका छात्रावास के बारे में आवश्यक सूचनाओं और उपयोगी जानकारी का समावेश किया गया है।
  - विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिये टीचिंग लर्निंग मैटेरियल से संबंधित गतिविधियों, जैसे- शिक्षक-विद्यार्थी डायरी, सभी प्रकार की वर्क बुक्स (उपचारात्मक रेडीनेस), कला एवं एबीएल किट, विज्ञान एवं गणित किट से संबंधित प्रमुख बातों को शामिल करते हुए एक विशेष वीडियो तैयार किया गया है।
  - वहीं बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण, आईसीटी लैब, व्यावसायिक शिक्षा गतिविधियाँ, सामुदायिक गतिशीलता (विद्यालयों के स्तर विकास समितियों की बैठक, सामुदायिक जागृति दिवस एवं आपणी लाडो योजना) तथा किशोर-किशोरी सशक्तीकरण गतिविधियाँ (राजू/मीना मंच, गार्गी मंच एवं अध्यापिका मंच, किशोरी मेला तथा चाइल्ड राइट क्लब) पर भी वीडियो बनाए गए हैं।
- विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों पर भी फोकस
  - विभाग द्वारा 'चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स'(विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों) के लिये ट्रांसपोर्ट भत्ता, एस्कॉर्ट भत्ता, स्टायफंड और रीडर भत्ता जैसी गतिविधियों का संचालन होता है। इनके बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी को एक वीडियो के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।
  - इसी प्रकार महात्मा गांधी स्कूलों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के वीडियो में एक्टिव कॉर्नर, रीडिंग कॉर्नर एवं कला कॉर्नर के साथ-साथ पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु टीएलएम (टीचिंग लर्निंग मैटेरियल) किट तथा विद्यार्थियों के लिये ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से संबंधित वीडियोज़ भी अब सभी के लिये यूट्यूब पर उपलब्ध हैं।
- कम अवधि के शिक्षक-प्रशिक्षण भी शामिल
  - विभाग में ब्लॉक और ज़िला स्तर पर एक या दो दिनों की छोटी अवधि के लिये कई शिक्षकों के कई प्रशिक्षण पूरे सत्र में आयोजित किये जाते हैं। इनमें शामिल होने के लिये टीचर्स को अपने स्कूलों से शहरों या फिर किसी अन्य सेंटर पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये यात्रा करनी पड़ती है। इससे उनको अनावश्यक परेशानी होती है और क्लास रूम टीचिंग पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है।

नोट :

- ऐसे में ब्लॉक एवं ज़िला स्तर पर चलने वाले ऐसे प्रशिक्षणों के बारे में भी वीडियो बनाए गए हैं, जिनको अपने मोबाइल पर अपनी सुविधा के अनुसार देख कर टीचर्स गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- इसके अलावा क्वालिटी एजुकेशन के लिये विद्यालय एवं शिक्षकों की परख से संबंधित एक वीडियो में निपुण मेला तथा शाला सिद्धि एवं शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र, क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल की जानकारी दी गई है।

राजस्थान विधानसभा में कई महत्त्वपूर्ण विधेयक ध्वनिमत से पारित

चर्चा में क्यों ?

2 अगस्त, 2023 को राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान विद्युत (शुल्क) विधेयक, 2023 सहित कई महत्त्वपूर्ण विधेयकों को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- प्रभारी मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने राजस्थान विद्युत (शुल्क) विधेयक, 2023 को सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया, जिस पर चर्चा के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2023 को सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया, जिस पर चर्चा के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
- सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक, 2023 को सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया, जिस पर चर्चा के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
- राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2023 को सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया, जिस पर चर्चा के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
- देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने नाथद्वारा मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2023 को सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया, जिसके बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

राज्यपाल ने 'संविधान को पढ़ो और जिओ'अभियान की शुरुआत की

चर्चा में क्यों ?

2 अगस्त, 2023 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में संस्कृति युवा संस्था के 'संविधान को पढ़ो और जिओ'अभियान की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु

- राज्यपाल कलराज मिश्र ने संस्कृति युवा संस्था द्वारा दो लाख की संख्या में मुद्रित 'संविधान की उद्देशिका और मूल कर्त्तव्य'संदेश का लोकार्पण भी किया।
- उन्होंने बताया कि राजभवन में संविधान उद्यान निर्माण के पीछे मंशा यही रही है कि संविधान की मूल प्रति और इसकी धाराओं को सहज, सरल ढंग में प्रदर्शित किया जाए। उन्होंने कहा कि संविधान की मूल प्रति शांतिनिकेतन के सुप्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस और उनके साथी कलाकारों ने तैयार की। इसमें राजस्थान के स्व. कृपाल सिंह शेखावत का भी महती योगदान रहा।
- संस्कृति युवा संस्था के पंडित सुरेश मिश्रा ने बताया कि संविधान की उद्देशिका और मूल कर्त्तव्यों की पालना की सीख के लिये संविधान जागरूकता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत दो लाख प्रतियों में राज्यपाल के संदेश के साथ संविधान की उद्देशिका और मूल कर्त्तव्यों का प्रकाशन किया गया है। इसे 'संविधान को पढ़ो और जिओ'अभियान के रूप में घर-घर जाकर प्रसारित किया जाएगा।

नोट :

'तारबंदी योजना' में प्रदेश पूरे देश में अव्वल

चर्चा में क्यों ?

2 अगस्त, 2023 को राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने विधानसभा में बताया कि किसानों की फसलों को आवारा पशुओं एवं अन्य जानवरों से सुरक्षा हेतु 'तारबंदी योजना' के तहत कृषकों को लाभान्वित करने की दृष्टि से राज्य देश में सबसे अव्वल है।

प्रमुख बिंदु

- कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने प्रश्नकाल में विधायकों की ओर से इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि तारबंदी योजना के तहत कृषकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से वर्ष 2023-24 में कुल 444.40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- उन्होंने बताया कि अभी तक योजना के अंतर्गत 4 करोड़ रुपए से अधिक व्यय किये गए हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि जो लक्ष्य निर्धारित हैं, उन्हें फसल कटाई के बाद पूर्ण किये जाने के प्रयास किये जाएंगें।
- उन्होंने कहा कि इस योजना से प्रभावित होकर अब उत्तर प्रदेश में भी योजना को शुरू किया जा रहा है, लेकिन वर्तमान में तारबंदी योजना के तहत किसानों की फसलों की जानवरों से सुरक्षा हेतु उनके खेतों के चारों तरफ तारबंदी करवाने के लिये राज्य सरकार की ओर से सहायता उपलब्ध कराने में प्रदेश पूरे देश में अव्वल है।
- इससे पहले विधायक नरेंद्र नागर के मूल प्रश्न के जवाब में कृषि मंत्री ने बताया कि योजना के प्रारंभ वर्ष 2017-18 से वर्ष 2022-23 तक कुल 69 करोड़ 66 लाख 42 हज़ार रुपए खर्च किये गए है।
- कटारिया ने बताया कि 3 वर्षों में विधानसभा क्षेत्र खानपुर में तारबंदी योजना के अंतर्गत 127 कृषकों को लाभान्वित किया गया है। उन्होंने लाभान्वित कृषकों का वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन के पटल पर रखा।

अंगदान महाअभियान की शुरुआत

चर्चा में क्यों ?

3 अगस्त, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अंगदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू किये गए अंगदान महाअभियान का शुभारंभ तथा इसके पोस्टर का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 771 करोड़ रुपए की लागत के 249 कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। साथ ही, मुख्यमंत्री ने दस चिरंजीवी 104 जननी एक्सप्रेस एंबुलेंस एवं 25 मोबाईल फूड टेस्टिंग लैब को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
- उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार नए ज़िला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र खोलकर स्वास्थ्य ढाँचे को सुदृढ़ किया गया है। स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू करने वाला राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है।
- उन्होंने कहा कि राज्य में 30 ज़िलों में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। शेष तीन ज़िलों में सरकार ने स्वयं के खर्चे पर मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला किया है। सभी ज़िलों में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है।
- मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नि:शुल्क पंजीकरण का दायरा बढ़ाकर सभी ई.डब्ल्यू. एस. तक करने की घोषणा की। इसके अनुसार सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति सहित सभी वर्गों के 8 लाख से कम आय वाले परिवारों की प्रीमियम राशि का भुगतान राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंगदाताओं के परिजनों तथा अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य के क्षेत्र में मॉडल स्टेट राजस्थान की थीम पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया।
- इस अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि प्रदेश में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 88 प्रतिशत परिवारों को कवर किया जा चुका है। 1.38 करोड़ परिवारों का बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा भरा जा रहा है।

नोट :

नोट :

नेशनल हैंडलूम वीक-2023

चर्चा में क्यों ?

3 अगस्त, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में बुनकरों, हथकरघा और खादी क्षेत्र के उत्पादों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किये जा रहे नेशनल हैंडलूम वीक-2023 का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य के हैंडलूम उत्पाद यहाँ की संस्कृति, विरासत और इतिहास को दर्शाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में भी हथकरघा एवं खादी की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। इन उत्पादों को विश्वस्तरीय पहचान दिलाने और एक बेहतर मंच दिये जाने के लिये प्रदेश में इस तरह का पहली बार आयोजन किया जा रहा है।
- विदित है कि जवाहर कला केंद्र में 3 से 7 अगस्त तक नेशनल हैंडलूम वीक-2023 का आयोजन किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हथकरघा कारीगरों की आमदनी बढ़ाने तथा उनके उत्थान के लिये प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी क्रम में एमएसएमई नीति-2022 में यह प्रावधान किया था कि इस प्रकार का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाएगा।
- इससे राज्य के हैंडलूम उत्पादों के प्रति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खरीदार आकर्षित होंगे। साथ ही, राज्य के हथकरघा बुनकरों व खादी के विभिन्न उत्पादों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।
- उन्होंने कहा कि यहाँ देश के विभिन्न राज्यों से हस्तशिल्पी और दस्तकार अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन और विक्रय कर सकेंगे। यह आयोजन मार्केटिंग की दृष्टि से बेहतर अवसर साबित होगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र के उत्पादों और उनसे जुड़े दस्तकारों के उत्थान के लिये राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति-2022 जारी की गई है। इस नीति से राज्य में हैंडलूम क्षेत्र में लगभग 50 हज़ार रोज़गार के नए अवसर सृजित होंगे।
- उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि बुनकरों की आबादी में लगभग 85 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। इनके उत्थान के लिये सरकार का उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान हथकरघा विकास निगम, बुनकर संघ, खादी बोर्ड, रुड़ा आदि के माध्यम से कई योजनाएँ और कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

नोट :

- राज्य सरकार द्वारा विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना-2023 लागू की गई है। इसके अंतर्गत महिलाओं, कामगार, हस्तशिल्पी, केश कला, माटी कला के दस्तकार और घुमंतू वर्ग के 1 लाख युवाओं को स्वयं का रोज़गार शुरू करने के लिये आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।
- अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) वीनू गुप्ता ने कहा कि राज्य में हथकरघा और खादी उत्पादों के लिये स्थाई मार्केटिंग की व्यवस्था हेतु सीधे क्रय करने वाली कंपनियों, बायिंग एजेंट, रिटेलर एसोसिएशन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मार्केटिंग कंपनियों को नेशनल हैंडलूम वीक-2023 में आमंत्रित किया गया है।
- इस पाँच दिवसीय आयोजन के दौरान हथकरघा और खादी उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिये 80 स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिनमें 70 स्टॉल्स में राज्य के खादी और हथकरघा उत्पादों तथा 10 स्टॉल्स में अन्य राज्य के बुनकरों के उत्कृष्ट उत्पादों का विक्रय और प्रदर्शन किया जाएगा।
- आयोजन में 10 राष्ट्रीय बुनकर पुरस्कार विजेता भी उपस्थित रहेंगे, जो कि अपनी असाधारण कृतियों का प्रदर्शन और बिक्री करेंगे।
- नेशनल हैंडलूम वीक के दौरान बायर-सेलर मीट, प्रदर्शनी, थीम पैवेलियन, टॉक शो, क्विज प्रतियोगिता, वर्कशॉप और सेमिनार के साथ-साथ राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 'फैशन शो' का आयोजन भी किया जाएगा।

नोट :

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट- राजस्थान को मिला बेस्ट हेरिटेज टूरिज़्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवॉर्ड

चर्चा में क्यों ?

6 अगस्त, 2023 को चेन्नई में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट में राजस्थान को पर्यटन विभाग के प्रतिनिधित्व में बेस्ट हेरिटेज टूरिज़्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवॉर्ड से नवाज़ा गया है।

प्रमुख बिंदु

- समारोह में राजस्थान पर्यटन विभाग की तरफ से उप निदेशक अजय शर्मा व पर्यटन अधिकारी सिराज कुरैशी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया।
- विदित है कि विश्व पटल पर राजस्थान अपनी कला-संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत, धार्मिक स्थलों, प्रसिद्ध मंदिरों, प्राचीन दुर्गों, महलों, स्वादिष्ट व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन स्थलों के लिये जाना जाता है।
- राजस्थान पर्यटन दल द्वारा एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से राज्य सरकार की ओर से पर्यटन क्षेत्र में उठाए गए कदमों, नवीन योजनाओं की जानकारी और पर्यटन प्रचार फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया।

मुख्यमंत्री ने दी स्वीकृति- राजस्थान राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड का हुआ गठन

चर्चा में क्यों ?

5 अगस्त, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- बोर्ड में 5 गैर-सरकारी सदस्य (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्य) होंगे। साथ ही उद्योग विभाग, स्कूल शिक्षा (प्राथमिक/माध्यमिक) एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, श्रम विभाग, देवस्थान विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव/आयुक्त/निदेशक/संयुक्त निदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि बोर्ड में सरकारी सदस्य के रूप में होंगे।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक स्तरीय अधिकारी बोर्ड में सचिव होंगे।
- राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि बोर्ड के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।
- बोर्ड का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा।
- राजस्थान राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड जोगी, योगी, नाथ जाति वर्ग की समस्याओं को चिह्नित कर प्रामाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा पिछड़ेपन को दूर करने के सुझाव राज्य सरकार को देगा।
- बोर्ड द्वारा समाज के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएँ प्रस्तावित करने, वर्तमान में संचालित योजनाओं के संबंध में विभिन्न विभागों से समन्वय करने, रोज़गार को बढ़ावा देने, समाज के शैक्षिक एवं आर्थिक उन्नयन, समाज के परंपरागत व्यवसाय को वर्तमान तौर-तरीकों से आगे बढ़ाने के संबंध में सुझाव दिये जाएंगे।
- साथ ही बोर्ड द्वारा समाज की धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर तथा मठों के सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्धार, समाज से संबंधित लेख, ग्रंथ, साहित्य आदि पर शोध, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध ठोस उपाय करने सहित अन्य सुझाव भी राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाएंगे।

दृष्टि The Vision

नोट :